Allocation of Funds for National Highway-49

*53. SHRI V. GOPALSAMY: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to refer to the answer to Unstarred Question No. 2141 given in the Rajya Sabha on 23rd August, 1995 and state:

(a) how much funds have been allotted and spent for investigation and survey of NH-49 till date;

(b) how far the survey and investigation has progressed since their sanctions;

(c) out of the provision of Rs. 31.06 crores for improvement of NH-49 during the Eighth Five Year Plan, how much amount has been allotted and spent in Kerala and Tamil Nadu respectively; and

(d) whether the Ghat section of NH-49 has been taken into consideration with special attention; if so, what steps have been taken to improve the condition of the highway in this section with details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI M. RAJASEKARA MURTHY): (a) and (b) Funds are allocated to States as a whole and not work-wise. An expenditure of Rs. 35.56 lakhs has been incurred on survey and investigation of Madurai-Cochin Section of NH-49 upto March 1995 and 80% work is complete.

(c) Out of the Eighth Five Year Plan provision of Rs. 31.06 crores for improvement of NH-49 (Madurai-Cochin Section), six estimates amounting to Rs. 2.93 crores have been sanctioned in Tamil Nadu. Further seven miscellaneous works (each costing less than Rs. 50 lakhs) amounting to Rs. 1.47 crores have also been sanctioned. In Kerala also 27 miscellaneous works (each costing less than Rs. 50 lakhs) amounting to Rs. 4.48 crores have been sanctioned during the Eighth Five Year Plan period.

(d) The overall improvement of the Ghat Section of NH-49 will be considered after completion of survey and investigation and subject to availability of funds. However, the road, including Ghat Section, is being kept in traffic-worthy condition with spot improvements and special repairs to accident prone reaches and bridges and culverts thereon.

Settlement of Indian claims by UN

*54. SHRI S. MUTHU MANI: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the United Nations released US Dollars 642,500 towards compensation in respect of settlement of 167 claims of Indians under 'B' category;

(b) whether any other Indian claims under other categories are still pending with the UN; and

(c) what action has been taken by Government to settle the claims of Indians and/or Indian companies by the UN Compensation Commission?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) to (c) Out of a total of 258 Category 'B' Indian claims sent to the United Nations Compensation Commission (UNCC) by 1.1.95 (the final extended date stipulated by the UNCC for receipt of claims in individual Categories A,B,C&D), the UNCC has released payment of US$642,500 for 167 Indian 'B' claims; the remainder of the 'B' claims were either rejected-found to be duplicate or transferred to Category 'C' by the UNCC. In respect of 28 'B' claims, additional medical/legal documents were required to be produced to the UNCC.

Apart from the payment for 167 successful Indian 'B' claims, the UNCC has so far approved for payment 60,320 Indian 'A' claims for US$236.27 million (ex-gratia payment for departure from Kuwait/Iraq), but the actual payment for these Indian 'A' claims is yet to be received from the UNCC. The UNCC has still to scrutinize the balance of the Indian 'A' claims and all 'C, 'D' and 'E'

claims as well as the Government of India's claim in Category 'F.

While it is the exclusive responsibility of the UNCC to examine and scrutinise and award payments to successful claimants, the Government of India have from time to time been impressing upon the Governing Council of the UNCC (comprising current members of the Security Council) to expedite settlement of Indian claims.

दूरसंचार तंत्र के विकास हेतु विदेशों के साथ करार

*55. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) दूरसंचार तंत्र के विकास और विस्तार के लिए आगमी तीन वर्षो के दौरान प्रति वर्ष प्रत्येक राज्य के लिए सरकार को कितनी धनराशि की आवश्यकता हैं;

(ख) क्या स्वीडन और अन्य देशों ने भारतीय दूरसंचार के विस्तार और विकास के कार्यक्रमों में भारत की सहायता करने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई समझौता किया गया हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और अन्य किन-किन देशों ने इस सम्बन्ध में रूचि दिखाई हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) वर्ष 1995-96 के लिए सर्किलवार बजट प्राक्कलन संलग्र विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिए) वर्ष 1996-97 के बजट प्रस्ताव योजना आयोग को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। सर्किलवार निधियों का आबंटन बजट की मंजूरी के बाद किया जाएगा। वर्ष 1997-98, जो नौंवी योजना का पहला वर्ष होगा, के लिए योजना के स्वरूप को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया हैं।

(ख) स्वीडन ने भारत के विकास कार्यक्रमों और दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार में सहायता करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं किया हैं। तथापि, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस और कनाडा से दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार और विकास के संबंध में कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) मद्रास में निष्पादित की जा रही नेटवर्क प्रबन्धन प्रणाली के लिए एक परियोजना जिसके लिए ऑस्ट्रेलियाई सहायता प्राप्त की गई हैं, के अलावा अभी तक कोई करार नहीं किया गया हैं।

निम्नलिखित प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं, जो सरकार के विचाराधीन हैं:-

जापान :

(i) ओ.ई.सी.एफ. ऋण की सहायता से दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार का प्रस्ताव।

(ii) ओ.ई.सी.एफ. जापान की अनुदान सहायता से उच्च स्तरीय दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र, गाजियाबाद, में सिंक्रोनस डिजिटल हैरारकी लैब की स्थापना का प्रस्ताव।

(iii)ओ.ई.सी.एफ. जापान की अनुदान सहायता से उपभोक्ता नेटवर्क में आप्टिकल फाइबर के इस्तेमाल के लिए उपस्कर की खरीद का प्रस्ताव।

कनाडा:

सी आई डी ए अनुदान की सहायता से उच्च स्तरीय दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र, गाजियाबाद, में प्रयोगशालायों के उन्नयन और प्रबन्धन संकाय को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव।

फ्रांस :

प्रयोगात्मक आधार पर सिंक्रोनस डिजिटल हैरारकी नेटवर्क की संस्थापना के लिए दूरसंचार विभाग के दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र और अल्टाटेल सीआईटी, फ्रांस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

विवरण

पूंजीगत कार्यो के संबंध में 1995-96 के बजट प्राक्कलनों के तहत निधियों का सर्किलचार आबंटन

(करोड़ रू. में)

क्रम सं.	**सर्किल का नाम**	**राशि**
1.	अण्डमान और निकोबार	4.00
2.	आंध्र प्रदेश	424.00
3.	असम	50.00
4.	बिहार	214.00
5.	गुजरात	414.00
6.	हरियाणा	175.00